Title: Need for reservation for Muslims in Government services - Laid.

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): महोदय, मुसलमानों को आर्थिक उत्थान कें अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनके बीच शिक्षा के प्रति कोई रुझान नही है। मुलमानों की सामाजिक दशा और आर्थिक दशा इस बात से जानी जा सकती है कि आजादी प्राप्ति के समय सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा था, जो वर्तमान समय में काफी घट गया है। उन्हें नौकरियों में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, जिसके कारण भारत में मुसलमान राष्ट्रीय धारा से कट गया और अपने आपको उपेक्षित महसूस करना लगा है। जबकि आज मानचित्र के किसी भी हिस्से में देखें, तो उनके हुनर देखने लायक हैं, परन्तु सरकारी नौकरियों में उनको हिस्सेदारी देनी होगी।

इसके लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारतीय सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण हेतु कानून बनाया जाए।